REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 15 | ISSUE - 11 | AUGUST - 2026

डॉलर की बादशाहत और डी-डॉलराइजेशन

डॉ. प्रशान्त
असिस्टेन्ट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र), बुंदेलखंड कॉलेज झाँसी.

सारांश –

प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक यूरोपीय देश की मुद्राओं विशेष कर पाउंड स्टर्लिंग करेंसी रिजर्व हुआ करती थी लेकिन 1929 की आर्थिक मंदी के बाद में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने तक अपनी फौजी और आर्थिक ताकत के बल पर अमेरिकी डॉलर ने पाउंड को विश्व कारोबार में पीछे धकेल दिया जो फिलहाल वर्तमान में भी कायम है। जब अंतरराष्ट्रीय वित्त बाजारों में अनिश्चित का समय होता है तो लोग डॉलर की तरफ भागते हैं क्योंकि डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुरक्षित ठिकाना माना जाता है वर्तमान में ऐसी मुद्रा की जरूरत है जो बेहतरी और स्थिरता लेकर आए चाहे वह डॉलर हो या कोई और मुद्रा ।

मुख्य शब्द – ब्रटेन-वुड्स,गोल्ड स्टैण्डर्ड, पेट्रोडॉलर, गोल्ड स्टैंडर्ड, फेडरल रिजर्व, डी-डॉलराइजेशन, ब्रिक्स, डॉलर-डिनॉमिनेटेड, निक्सन शॉक, जीनियस एक्ट, स्टेबलकॉइन ।

परिचय

अमेरिका में कागजी मुद्रा के पहले दस्तावेजी उपयोग का पहला प्रमाण 1690 में मिलता है, जब मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी द्वारा औपनिवेशिक नोट जारी किए गए थे। इन नोटों का उपयोग सैन्य अभियानों के लिए धन जुटाने के लिए किया जाता था। पहला दो डॉलर का नोट 1776 में जारी किया गया और नौ साल बाद अमेरिका के कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया । डॉलर को नए- नए आजाद हुए अमेरिका की आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की घोषणा की। 1785 में, अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर डॉलर चिह्न को अपनाया, जिसके लिए स्पेनिश-अमेरिकी पेसो के प्रतीक का उपयोग मार्गदर्शक के रूप में किया गया। तब संस्थापकों ने एक आधार-दस मुद्रा प्रणाली को अपनाया , जिसमें दस सेंट मिलकर एक डाइम बनाते हैं,और दस डाइम मिलकर एक डॉलर बनाते हैं । अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने फेडरल रिजर्व की स्थापना से एक दशक से भी अधिक समय पहले,1890 में देश की वैधानिक मुद्रा जारी करना शुरू किया था।

1889 में अमरीकी पत्रकार नेली ब्लाई ने जूल्स बर्न से प्रेरित होकर 80 दिनों में विश्व का चक्कर लगाने का संकल्प लिया। इस विश्व यात्रा पर निकलने से पहले उन्होंने अपने बैग में अमरीकी सोने के सिक्के और ब्रिटिश पौंड रखे। जब वह यात्रा करते हुए श्रीलंका पहुँची तो कुछ सामान खरीदने के लिए अमेरिकी सिक्के निकालती है लेकिन दुकानदार ने अमेरिकी सोने के सिक्के लेने से इनकार कर दिया तब नेली ब्लाई को अमेरिकी सिक्के 60% छूट पर देने पड़े लेकिन ब्रिटिश पौंड आसानी से चल रहे थे। इस समय तक अमेरिका एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था थी तथा उसने यूरोप के बड़ी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन ब्रिटिश पौंड की तरह अमरीकी डॉलर की पहचान नहीं थी, उस समय स्थिति यह थी कि डॉलर घर में ही डाँवाडोल हाल में था। अमेरिका में गृह युद्ध से पहले कोई केंद्रीय बैंक नहीं था कोई भी बैंक रेलवे कंपनी यहां तक की दवाई की कोई बड़ी फार्मेसी भी अपना नोट छाप सकती थी इसका नतीजा या था कि हजारों की संख्या में अलग-अलग संस्थाएं नोट छाप रही थी। बाजार में हजारों तरीके की बनावट के नोट घूम रहे थे किसी नोट पर खेत खलिहान किसी पर सांता क्लास तथा कई तो अजीबोगरीब तस्वीरों वाले भी थे लेकिन चार्ज वाशिंगटन की तस्वीर वाले डॉलर के नोट बाद में आए। न्यूयॉर्क के बैंक का नोट लेकर शिकागो जाने पर दुकानदार 20-30 फ़ीसदी काट लेते थे या लेने से मना कर देते थे लोग दुकानों पर सामान खरीदने के पहले "बैंक रिपोर्ट" नाम की साप्ताहिक पत्रिका पढ़ते थे कि किस राज्य के नोट की कीमत क्या है बैंक अपना हिसाब सोने में करते थे शुक्रवार के दिन बैंक के कर्मचारी थैलों में सोना लेकर अलग-अलग बैंकों में हिसाब क्लियर करते थे कभी-कभी तो यह थैले फट जाते थे और चोर लुटेरे इन्हें लूट लेते थे l

1907 में अमेरिका में एक भयंकर वित्तीय संकट आता है और शेयर बाजार 50% से ज्यादा गिर जाता है तब सभी लोग बैंकों से पैसा निकालने दौड़ पड़ते हैं और इस आपाधापी में बैंक डूबने लगते हैं इस संकट की घड़ी में जेपी मॉर्गन सामने आते हैं जो उसे समय के सबसे ताकतवर बैंकर थे इन्होंने न्यूयॉर्क में 50 बड़े बैंकरों को अपनी निजी लाइब्रेरी बुलाया तथा मैराथन प्रयास करके 1913 में बनी फेडरल रिजर्व की नींव डाली। फेडरल रिजर्व बैंक की स्थापना से मुद्रा प्रणाली की अविश्वसनीयता और अस्थिरता का समाधान किया। इस समय तक डॉलर घरेलू मुद्रा के रूप में मजबूत हो चुका था लेकिन वैश्विक करेंसी के रूप में ब्रिटिश पाउंड का प्रभुत्व अभी भी बना हुआ था l लेकिन प्रथम विश्व युद्ध खत्म होते-होते और 1929 की ग्रेट डिप्रेशन ने अमेरिका में बैंकों और शेयर बाजार को भारी नुकसान पहुंचा,अर्थव्यवस्था मंदी में चली गई तथा बेरोजगारी चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। लोगों का फिर से डॉलर से भरोसा जाता और लोगों ने सोना मांगना शुरू कर दिया लेकिन बैंकों के पास पर्याप्त सोना नहीं था। अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति में 5 अप्रैल 1933 को राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक सरकारी आदेश के तहत हर नागरिक, हर कंपनी बैंक को सोना सरकार के पास जमा करने का आदेश दिया तथा ऐसा न करने पर जुर्माना के साथ 10 साल की सजा का आदेश पारित किया इस आदेश के तहत लोगों ने अपना सोना सरकारी तिजोरियों में जमा कर दिया। रूजवेल्ट में एक अप्रत्याशित फैसला लेते हुए $20 में खरीदे गए सोने की कीमत बढ़ाकर $35 कर दी इससे सोने के मुकाबले डॉलर की कीमत गिर गई जिससे अमेरिका का निर्यात बढा और फैक्ट्रियां तीव्र गति से दौड़ने लगी बेरोजगारी कम होने लगी तथा विश्व का सोना बहकर अमेरिका की फोर्ड नॉक्स की तिजोरी में आ गया l

ब्रटेन वुड्स समझौते से गोल्ड स्टैण्डर्ड ध्वस्त होने तक

अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व की जड़े प्रथम विश्व युद्ध से मजबूत होनी शुरू हो गई थी लेकिन इसका शिखर द्वितीय विश्व युद्ध में जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हुए हमले के बाद पूरी तरह स्थापित हो गई। पर्ल हार्बर पर आक्रमण से पहले अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में सीधी दखल से बच रहा था लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विस्टन चर्चिल यह चाहते थे कि अमरीका द्वितीय विश्व में सीधी दखल दे। लेकिन जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर किए गए हमले के बाद विस्टन चर्चिल जंगी जहाज लेकर अमेरिका पहुंच गए और महीने भर के भीतर अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया lअमेरिका अगर द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल न हुआ होता तो यूरोप का राजनीतिक भूगोल कुछ और ही होता। जुलाई 1944 में ब्रटेन वुड्स समझौता हुआ गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ (अमेरिकी डॉलर और सोने की विनिमय दर)आया। इसी समझौते के बाद विश्व के देशों ने अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार बनाना शुरू किया 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही दुनिया में डॉलर का परचम लहरा चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब रक्तपात रुका और शांति की जरूरत महसूस हुई तब नई अर्थव्यवस्था की मेजबानी ब्रटेन वुड्स समझौते को मिली इसी समझौते ने विश्व बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाओं की बुनियाद रखी। इस समझौते में एक औंस सोने के बदले 35 अमेरिकी डॉलर यही था यही गोल्ड स्टैंडर्ड था। यह जिम्मेदारी अमेरिका पर थी कि वह हर परिस्थिति में इस स्टैंडर्ड को कायम रखें इसका अर्थ यह था कि अगर सोने की विनिमय में दर 35 डॉलर से नीचे जाती है तो अमेरिका डॉलर छापकर इस कमी को पूरा करके संतुलित करता था ब्रिटिश पाउंड, जर्मन मार्क, फ्रैंक का विनिमय आधार भी डॉलर हो गया। 1960 तक सब कुछ ठीक चलता रहा लेकिन वक्त ने करवट ली जापान और यूरोपीय यूनियन का विश्व व्यापार में हिस्सा तेजी से बड़ा और अमेरिका का हिस्सा घटने लगा दुनिया के देश डॉलर के बदले सोने के लिए दबाव बनाने लगे। इसी समय के वियतनाम युद्ध में फंसने के कारण अमेरिका ने रक्षा खर्च में बढ़ोतरी हुई और करेंसी छापी गई और पानी की तरह डॉलर बहाया गया। अमेरिका में सोने की आपूर्ति तो बढ़ नहीं रही थी lतब एक वक्त आया जब डॉलर की संख्या ज्यादा हो गई और सोना काम पड़ गया यही वह मुकाम था जब मुद्रा बाजार में रोमांचक घटनाक्रम शुरू हुए l युरोप के तेज तर्रार नेता और फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डि गॉल ने इस स्थिति को सबसे पहले समझा और अमेरिका से डॉलर के बदले सोना लेना शुरू कर दिया। फ्रांस ने 15 करोड डॉलर की बदले अपना सोना अमेरिका से ले चुका था फिर यह बात सार्वजनिक हो गई और यूरोप के अन्य देशों में भी डॉलर के बदले सोना मांगना शुरू कर दिया। सभी देश तो नहीं लेकिन स्पेन ने भी अच्छा खासा अपना सोना डॉलर के बदले ले लिया। बाजार में सोने की कीमत में उबाल आ गया अक्टूबर 1960 में सोने की कीमत $40 पर औंस प्रति डॉलर हो गई अमेरिका के दबाव में ब्रिटेन,पश्चिमी जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्वीटजरलैंड, नीदरलैंड ने मिलकर लंदन गोल्ड पूल बनाया। इन देशों ने सोने के भंडारों का इस्तेमाल करके गोल्ड स्टैंडर्ड को बचाने की कोशिश की अर्थात 35औंस की कीमत को बनाए रखने की पूरी कोशिश की यह पूल 6 सालों तक चला लेकिन 1966 में फ्रांस ने इसे नाता तोड़ लिया और गोल्ड पूल डह गया और गोल्ड स्टैंडर्ड के दिन लद गए l फेडरल रिजर्व बैंक ने नौ केंद्रीय बैंकों के साथ मिलकर स्वैप की सुविधा शुरू की इसमें ब्रिटेन,जर्मनी, इटली, फ्रांस, और कनाडा प्रमुख थे। इन देशों कोशिश डॉलर के बदले सोने की मांग को सीमित और संतुलित करना था। लेकिन तब तक अमेरिकी मौद्रिक सिस्टम की दरारें खुल चुकी थी। सोना कम था और डॉलर की भरमार थी तथा गोल्ड स्टैंडर्ड का अंत आ चुका था। 1971 में अमेरिकी

राष्ट्रपति निक्सन ने डॉलर की सोने से परिवर्तनीयता खत्म कर दी डॉलर को सोने बदलने की नीति समाप्त कर दी। अमेरिका में आयात पर 10% ड्यूटी लगा दी तथा अमेरिका द्वारा विदेशों को दी जाने वाली सहायता में भी कटौती कर दी गई। इस प्रकार द्वितीय युद्ध के बाद बनी मौद्रिक व्यवस्था ढह गई सोना दुनिया की आधारभूत या फिएट करेंसी नहीं रही। एक नई मौद्रिक प्रणाली आई डॉलर आधारभूत मुद्रा थी डॉलर फिएट करेंसी हो गई। दुनिया की मुद्रा अब सोने पर आधारित नहीं थी इस कारण इसमें तेज उतार चढ़ाव होने से इस व्यवस्था का लाभ यह था कि अर्थव्यवस्था की सुविधा के अनुसार करेंसी छापी जा सकती थी। इसी के साथ अमेरिका की नई मौद्रिक प्रणाली का स्वागत ग्रेट इन्फ्लेशन के साथ हुआ एवं विश्व की मौद्रिक प्रणाली में बहुत कुछ बदल गया।

योम किप्पुर युद्ध -पेट्रोडॉलर समझौता और प्लाजा एकॉर्ड

1973 के योम किप्पुर युद्ध और उसके बाद पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन द्वारा लगाए गए तेल प्रतिबंध के कारण कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू गईं। प्रमुख तेल उत्पादकों के आर्थिक प्रभाव को पहचानते हुए, अमेरिकी हेनरी किसिंजर ने 1974 में सऊदी अरब की यात्रा की और एक रणनीतिक पेट्रोडॉलर समझौते पर बातचीत की इस समझौते सऊदी अरब ने अपने कच्चे तेल के निर्यात का मूल्य निर्धारण केवल अमेरिकी डॉलर में करने पर सहमति व्यक्त की। बाद में अन्य ओपेक सदस्यों ने भी इसी पद्धति को अपनाया। अरब ने अपने अधिशेष तेल राजस्व को अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड और अमेरिकी वित्तीय बाजारों में वापस निवेश करने पर सहमति व्यक्त की। इसके बदले में, अमेरिका ने सऊदी शासन को व्यापक सैन्य सुरक्षा, हथियार और आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान की l तेल विश्व की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होने के कारण, इस प्रणाली के तहत सभी आयातक देशों को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार बड़ी मात्रा में अमेरिकी डॉलर का भंडार रखना आवश्यक था। इस संरचनात्मक मांग ने डॉलर को निर्विवाद वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में स्थापित किया। अमेरिका के लिए, इसने सरकारी ऋण के लिए सस्ता वित्तपोषण प्रदान किया, लगातार व्यापार घाटे को संभव बनाया और फेडरल रिजर्व को वैश्विक आर्थिक बाजारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की अनुमति दी।

मार्च 1974 में ऑयल इम्बार्गो खत्म होने तक महगाई अपने चरम पर पहुँच गई 1980 अमेरिका महगाई 15% तक थी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने महगाई रोकने के लिए ब्याज दरें 20% तक पंहुचा दी। इस कारण डॉलर इंडेक्स मजबूत होने लगा। 1979 में जो डॉलर इंडेक्स 85 के पास था वह 1986 में 160 अंक पर जा पहुँचा। इस कारण अमेरिका मंदी- बेरोजगारी में फसने लगा। अमेरिकी निर्यात दुनियाँ भर में पिट रहे थे। राष्ट्रपति रीगन को अमेरिकी डॉलर की ताकत घटने पर मजबूर होना पड़ा और दुनिया को एक ऐसा समझौता मिला जिसकी मिसाल मिल पाना अब संभव नहीं है वह समझौता 22 सितंबर 1985 को हुआ के ऐतिहासिक प्लाजा होटल में पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच प्लाजा समझौता हुआ जी 5 देशों ने अमेरिका को डॉलर के 50 फ़ीसदी अवमूल्यन पर राजी कर लिया l जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान की मुद्राओं का मूल्य करीब इतना ही बढ़ गया l केंद्रीय बैंक ने मुद्रा बाजार में सीधा हस्तक्षेप किया लेकिन यह समझौता जापान पर भारी पड़ा क्योंकि इसके बाद जापान की अर्थव्यवस्था लम्बी मंदी और डिफ्लेशन में धस गई l प्लाजा समझौता लंबा नहीं चला दो साल बाद फरवरी 1987 में फ्रांस के लूव्र में नई संधि से इसे रद्द कर दिया गया l जी 5

देश के केन्दीय बैंकों ने विदेशी मुद्रा बाजार में दखल बंद कर दिया महंगाई थम गई लेकिन अमेरिकी मुद्रा की मजबूती डॉलर में कर्ज लेने वालों पर भारी पड़ी l1994 में मैक्सिकन पेसों का भारी अवमूल्यन हुआ यही टकीला क्राइसिस था l विदेशी निवेशक बाजार से पैसा निकालने लगे अमेरिका और आईएमएफ ने मेक्सिको की मदद की मजबूत डॉलर की मार जुलाई 1997 थाईलैंड,फिलिपींस और इंडोनेशिया में आए संकट आए घरेलू मुद्राओं का भारी अवमूल्यन हुआ विदेशी पूंजी उड़ने लगी और शेयर बाजारों का बुरा हाल हो गया 1987 के बाद से अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने 1990 के पूरे दशक में ब्याज दरे कम की तब जाकर 1995 में डॉलर इंडेक्स 81 पर आया l 1998 की डॉट कॉम बुलबुले की आहट के बीच 1998 में ब्याज दरे फिर बढ़ने लगी इसके चलते नवंबर 1999 से जुलाई 2000 के बीच डॉलर इंडेक्स 117 से जा लगा अमेरिका पर आतंकी हमले के बाद फेड ने ब्याज दरे कम की तब जा कर डॉलर इंडेक्स कम हुआ तो डॉलर की ताकत नरम पड़ने लगी l

डॉलर की बादशाहत के कारण

1944 में ब्रेटन वुड्स में हुई बहस में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स और अमेरिकी वित्त अधिकारी हैरी डेक्सटर व्हाइट आमने-सामने थे, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को निर्धारित किया। कीन्स एक पूरी तरह से नई, तटस्थ अंतरराष्ट्रीय आरक्षित मुद्रा चाहते थे जिसे "बैंकर" कहा जाता था l जिसका प्रबंधन एक वैश्विक केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता था, कीन्स का उद्देश्य कर्ज में डूबे ब्रिटिश साम्राज्य को कर्जदार देशों को अधिक मतदान शक्ति और तरलता देकर उसकी रक्षा करना था। व्हाइट ने इस प्रणाली को सोने द्वारा समर्थित अमेरिकी डॉलर से जोड़ने के लिए ज़ोरदार तर्क दिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था था,विश्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति और वैश्विक स्वर्ण आपूर्ति के अधिकांश हिस्से पर उसका नियंत्रण था इसलिए यह प्रणाली को अमेरिकी वित्तीय वर्चस्व स्थापित करने के लिए तैयार किया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रमुख मुद्रा निर्णयों पर अमेरिका के पास निर्णायक शक्ति हो अन्ततः तर्क में कीन्स आगे थे लेकिन नियम हमेशा ताकतवर के हिसाब से ही चलते है l इस ताकत का प्रयोग अमरीका समय-समय पर विश्व के कई देशों पर आर्थिक प्रतिबन्ध लग्गता है। 2005 में मकाऊ के एक बैंक पर शक था कि वह उत्तर कोरिया के लिए काम कर रहा है, अमेरिका के वित्त विभाग के आदेश पर इस बैंक से लेनदेन न करने की सूचना जारी की गई और यूरोप से लेकर एशिया तक सभी बैंकों ने उससे अपने रिश्ते तोड़ लिए और कुछ ही दिनों में वह बैंक डूबने की कगार पर आ गया। करोड़ों डॉलर का फंड फ्रिज हो गया। 2012 में ईरान के साथ ही हुआ स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर होने के कारण तेल निर्यात आधा हो गया अर्थव्यवस्था चरमरा गई ठीक यही हाल रूस का 2022 में हुआ जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया।

द्वितीय विश्व युद्ध के समय ग्लोबल जीडीपी में अमरीका की भागेदारी 45% थी जो वर्तमान में घटकर 25% रह गयी है इनके बावजूद भी डॉलर का प्रभुत्व अभी भी बना हुआ है l

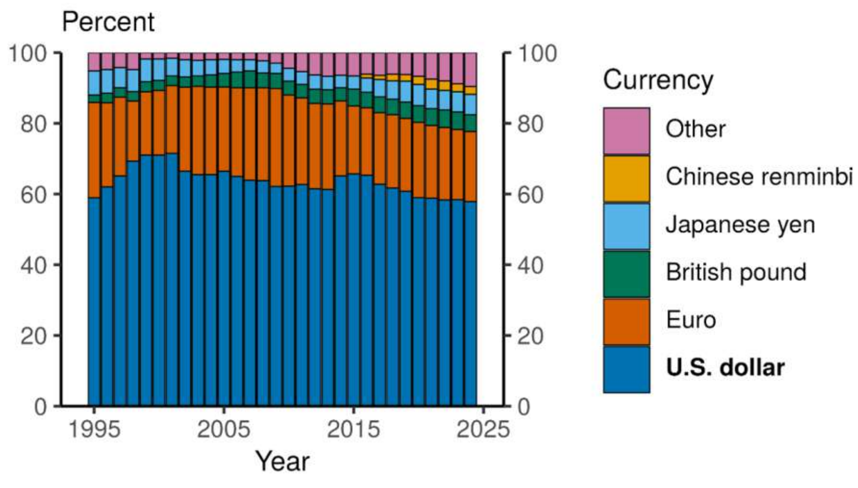

चित्र-1स्रोत:आईएमएफ,फेडरल रिज़र्व,ब्लूमबर्ग

वैल्यू

को सुरक्षित रखने के साधन के तौर पर अमेरिकी डॉलर पर लोगों का बहुत भरोसा है। करेंसी का एक मुख्य काम वैल्यू को सुरक्षित रखना है, जिसे भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए बचाया जा सके और जिसकी खरीदने की क्षमता (परचेजिंग पावर) में कोई खास कमी न आए। किसी करेंसी पर वैल्यू सुरक्षित रखने के साधन के तौर पर भरोसे का एक पैमाना यह है कि उसका इस्तेमाल सरकारी विदेशी मुद्रा भंडार में कितना होता है। जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है, 2024 में घोषित ग्लोबल सरकारी विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी 58 प्रतिशत थी। यह अन्य सभी करेंसी से कहीं ज़्यादा थी। 2001 में डॉलर की हिस्सेदारी भंडार का 72 प्रतिशत थी, जो अब कम हो गई है, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार मैनेजर्स ने अपने पोर्टफोलियो में कई छोटी करेंसी, जैसे ऑस्ट्रेलियाई और कनाडाई डॉलर को भी शामिल किया है । इस गिरावट के बावजूद, डॉलर अब भी सबसे बड़ी रिज़र्व करेंसी बनी हुई है और इसकी हिस्सेदारी लगभग उतनी ही है जितनी 1995 में थी। खास बात यह है कि 2022 से इसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ है

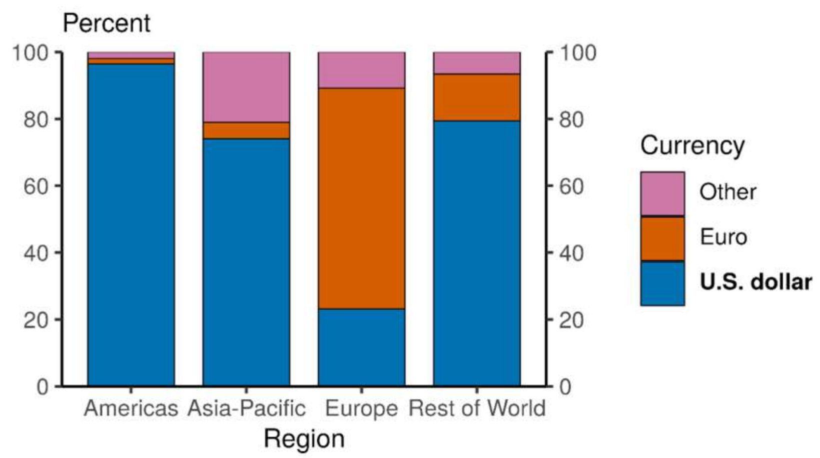

चित्र-2. स्रोत:आईएमएफ,फेडरल रिज़र्व,ब्लूमबर्ग

किसी करेंसी की अंतरराष्ट्रीय भूमिका को इस आधार पर भी मापा जा सकता है कि उसका इस्तेमाल लेन-देन के माध्यम के तौर पर कितना होता है। ग्लोबल ट्रेड और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेन-देन में करेंसी के इस्तेमाल के मामले में अमेरिकी डॉलर के दबदबे को दिखाया गया है। ग्लोबल ट्रेड में डॉलर दुनिया की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी है। ग्लोबल ट्रेड इनवॉइस में डॉलर की हिस्सेदारी का अनुमान चित्र 2 में दिखाया गया है। अमेरिका में ट्रेड इनवॉइसिंग का 96 प्रतिशत, एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में 74 प्रतिशत और बाकी दुनिया में 79 प्रतिशत हिस्सा डॉलर का था। इसका एकमात्र अपवाद यूरोप है।

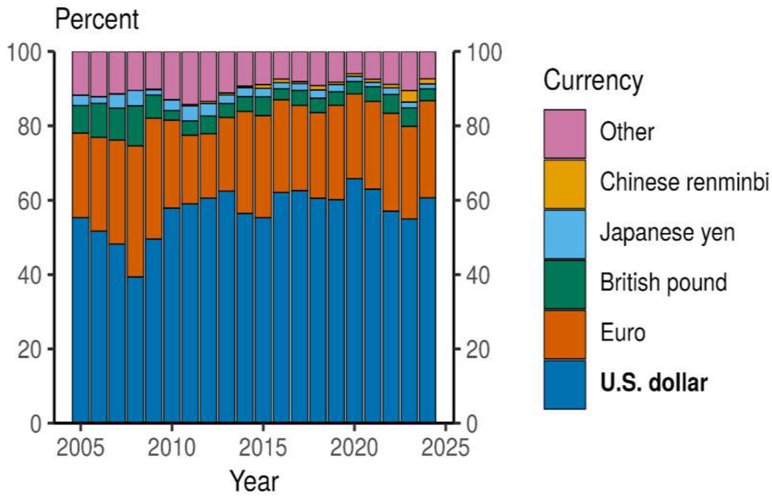

चित्र-3.स्रोत:आईएमएफ,फेडरल रिज़र्व,ब्लूमबर्ग

विदेशी मुद्रा में लिए गए कर्ज़—यानी कंपनियों द्वारा अपने देश की मुद्रा के अलावा किसी दूसरी मुद्रा में लिया गया कर्ज़—के मामले में भी अमेरिकी डॉलर का दबदबा है। जैसा कि चित्र 3 में दिखाया गया है, 2010 से डॉलर में लिए गए विदेशी मुद्रा कर्ज़ का हिस्सा लगभग 60 प्रतिशत बना हुआ है। इस वजह से डॉलर, यूरो से काफी आगे है, जिसका हिस्सा 26 प्रतिशत है।

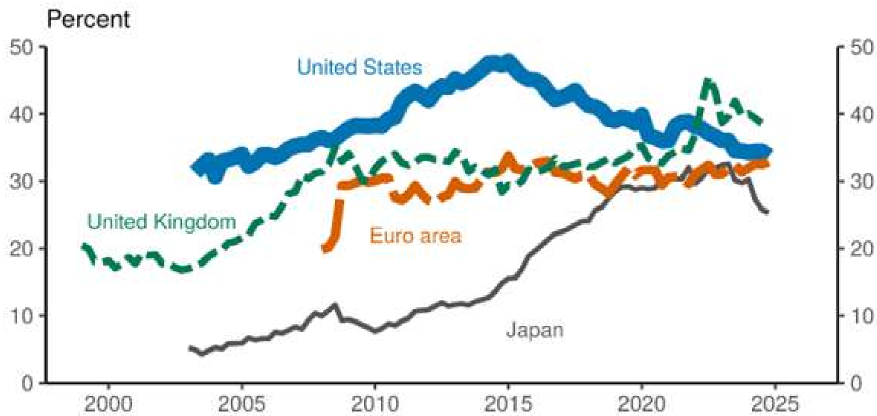

चित्र-4.स्रोत :आईएमएफ,फेडरल रिज़र्व,ब्लूमबर्ग

अमेरिकी डॉलर के आधिकारिक भंडार का अधिकांश हिस्सा अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिभूतियों के रूप में रखा गया है, जिनकी आधिकारिक और निजी दोनों प्रकार के विदेशी निवेशकों द्वारा अत्यधिक मांग है।जबकि 55 प्रतिशत हिस्सा घरेलू निजी निवेशकों के पास और 13 प्रतिशत हिस्सा फेडरल रिजर्व सिस्टम के पास था। हालांकि विदेशी निवेशकों द्वारा धारित ट्रेजरी प्रतिभूतियों का हिस्सा 2014 में लगभग 50 प्रतिशत से घटकर, ट्रेजरी प्रतिभूतियों में विदेशी हिस्सेदारी 2022 से लगभग अपरिवर्तित है (चित्र-4)और यूरो क्षेत्र, जापान और यूनाइटेड किंगडम की सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में विदेशी हिस्सेदारी के लगभग बराबर है।

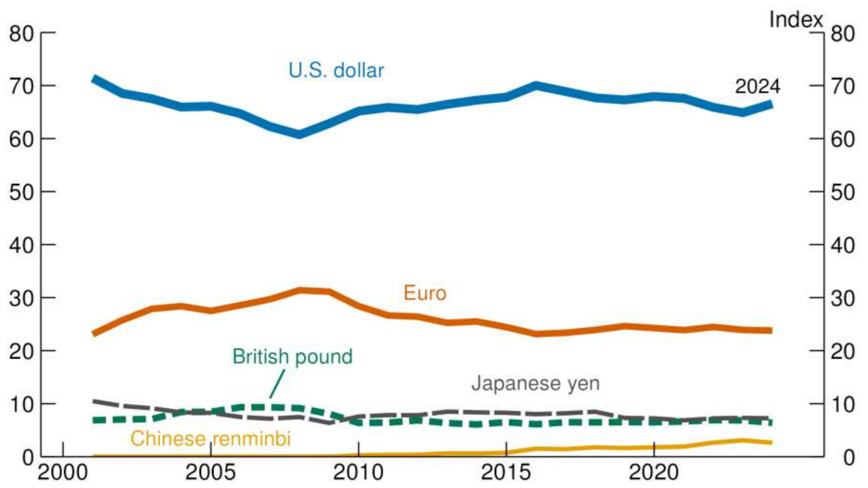

चित्र-5.स्रोत:आईएमएफ,फेडरल रिज़र्व,ब्लूमबर्ग

2010 से डॉलर इंडेक्स का स्तर 65 से 70 के बीच एक सीमित दायरे में रहा है, जो बाकी सभी मुद्राओं से काफी आगे है। यूरो का मूल्य इसके बाद सबसे ज़्यादा, लगभग 24 है, और इसका मूल्य भी काफी हद तक स्थिर रहा है। हालांकि चीनी रेनमिनबी का अंतरराष्ट्रीय इस्तेमाल बढ़ा है, लेकिन यह इंडेक्स में लगभग 3 के स्तर तक ही पहुंच पाया है, जो जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड से पीछे है; ये दोनों मुद्राएं क्रमशः लगभग 7 और 6 के स्तर पर हैं। कुल मिलाकर, पिछले 20 वर्षों में अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व स्थिर बना हुआ है।

डी-डॉलराइजेशन और ब्रिक्स

डी-डॉलराइजेशन का उद्देश्य वैश्विक बाजार में अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक प्रभुत्व को कमजोर करना है जिसके कारण वैश्विक व्यापार,वित्तीय लेनदेन ,डॉलर- डिनॉमिनेटेड परिसम्पत्तियों में हिस्सेदारी में कमी, रिजर्व मुद्रा के रूप में डॉलर की महत्ता के प्रभाव में उल्लेखनीय कमी लाना। डॉलर पर अत्याधिक निर्भरता के कारण अमेरिकी मौद्रिक नीति का नकारात्मक प्रभाव कई देशो में मुद्रा अवमूल्यन, ऋण की लागत में वृद्धि, मुद्रास्फीति में भारी वृद्धि के रूप में देखने को मिलती है। इसके इतर अमेरिकी डॉलर और पेमेंट क्लीयरिंग प्रणालियों का हथियार के रूप में प्रयोग करके देशों की नीतियों और सरकार के संचालन पर असर के कारण बाजार में अनिश्चितता और अस्थिरता पैदा करते है जिसके कारण व्यापार और निवेश प्रभावित होता है। डी-डॉलराइजेशन की सबसे संगठित और रणनीतिक पेशबंदी चीन के तरफ से शुरू हुई है। चीन दुनिया का इकलौता देश है जहां उसकी करेंसी का अंतरराष्ट्रीयकरण करने का एक पूरा अलग से विभाग है जिसे युवान इंटरनेशनल

डिपार्टमेंट कहते हैं यह डिपार्टमेंट चीन ने 2015 में बनाया था। चीन डी-डॉलराइज़ेशन को बढ़ावा देने के लिये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और अपनी डिजिटल मुद्रा का उपयोग करने का प्रयास कर रहा है। उसने हॉन्गकॉन्ग, सिंगापुर और यूरोप में युवान ट्रेडिंग सेंटर स्थापित किये हैं। वर्ष 2021 में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अपनी डिजिटल मुद्रा ई-युआन के माध्यम से वैश्विक वित्तीय नियमों को प्रभावित करने के लिये 'बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स' के समक्ष 'ग्लोबल सॉवरेन डिजिटल करेंसी गवर्नेंस' का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पहले ही वर्ष 2016 में युआन को अपने विशेष आहरण अधिकार बास्केट में शामिल कर लिया है।अमेरिकी स्विफ्ट को बायपास करते हुए रूसी 'एसपीएफएस' एवं चीनी 'सिप्स' को संयुक्त कर एक नई रूस-चीन भुगतान प्रणाली की संभावित शुरुआत हेतु प्रयास चल रहे हैं।

चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग क्षमता वाला देश है, ऊर्जा का सबसे बड़ा आयातक है, विश्व के व्यापार में सबसे बड़ी भागीदारी है, डॉलर का सबसे बड़ा रिज़र्व है, अपनी इन्ही क्षमताओं का प्रयोग करके तथा रूस के साथ सहयोग से करेंसी के छोटे-छोटे समूह बनाकर युवान के अंतरराष्ट्रीयकरण की ओर आक्रामक ढंग से आगे बढ़ रहा है। चीन ने शंघाई कॉरपोरेशन काउंसिल जिसकी बैठक समरकंद में हुई थी में चीन ने रूस और ईरान के साथ त्रिपक्षी समझौता करके अपनी मुद्राओं में एक दूसरे के साथ व्यापार को सुगम बनाने की दिशा में समझौते किए है चीन पाकिस्तान एवं कई छोटे देशों के केंद्रीय बैंक के साथ क्लीयरिंग तथा स्वैप का समझौता किया है जिसका अर्थ यह है कि ये देश अपने यहां युवान का रिज़र्व बना सकते है और चीन से सामान वस्तु एवं सेवाएं खरीद सकते है। चीन मुश्किल में फंसे छोटे-छोटे देश को कर्ज देने के लिए अपने फॉरेक्स रिजर्व का प्रयोग करता है इन्हीं सब आक्रामक घटनाक्रमों से हम अंदाजा लगा सकते हैं चीन निकट भविष्य में विकासशील देश में अपनी करेंसी का प्रचार प्रसार जरूर अच्छे से कर सकेगा।

ब्रिक्स के व्यापार में मुद्रा का वितरण

भागीदार देश	व्यापार मूल्य	$डॉलर का भाग	युवान का भाग	अन्य
रूस –चीन	$240 बिलियन	20%	**62%**	18%
रूस -भारत	$75 बिलियन	**78%**	12%	10%
चीन – ब्राजील	$166 बिलियन	88%	11%	1%
चीन –सऊदी	$115 बिलियन	92%	5%	3%
भारत –चीन	$136 बिलियन	89%	9%	2%
ब्राजील –भारत	$18 बिलियन	95%	2%	3%
ब्रिक्स +औसत	$1.85 ट्रिलियन	**68%**	21%	11%

सारणी :-1 स्रोत: अंकटाड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड रिपोर्ट, ब्रिक्स

ब्रिक्स संगठन जो डॉलर को चुनौती देने के तैयारी कर रहा है का आपसी व्यापार 68% अभी भी डॉलर में होता है, सिर्फ चीन और रूस ही ऐसे देश है जिनका 62% व्यापार युवान में होता है ऐसा रूस के यूक्रेन युद्ध में उलझने तथा चीन के रूस पर बढते आर्थिक प्रभाव के कारण है। एक व्यापार की मुद्रा के तौर पर युवान के महत्व

को इनकार नहीं किया जा सकता है लेकिन वैश्विक नियम कानून के आधार पर युवान वैश्विक मुद्रा बनने की कोई शर्त पूरी नहीं करता है क्योंकि पूंजी का निवेश डॉलर की तुलना में युवान कहीं नहीं टिकता है पूंजीगत जो निवेश है वह ज्यादातर या तो यूरो में है या तो डॉलर में है दूसरी बात चीन अपने निर्यात को सस्ता रखने के लिए अपनी मुद्रा के मूल्य को लगातार कम रखता है अर्थात चीन की अर्थव्यवस्था में वित्तीय पारदर्शिता नहीं है चीन की अर्थव्यवस्था में भारत जितनी भी पारदर्शिता नहीं है अमेरिका चीन को हमेशा मुद्रा के मैनुपुलेटर की लिस्ट में रखता है इससे चीन की मुद्रा पर वैश्विक मुद्रा बनने की जो पारदर्शिता और स्पष्टा चाहिए वह उपलब्ध नहीं है।

डॉलर का नया अवतार

2008 के आर्थिक संकट के बाद उस वक्त सरकारें आर्थिक संकट से जिस प्रकार से निपटीं, उससे कई लोग नाराज़ थे, बाद में उन नाराज तकनीकी पेशेवरों ने क्रिप्टोकरेंसी बनाई क्योंकि उन्हें लगा कि एक ऐसी मुद्रा होनी चाहिए जो किसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी न हो और न ही उस पर किसी सरकार का नियंत्रण हो। अपने उदभव के साथ ही क्रिप्टोकरेंसी ने डिजिटल वित्त के भविष्य के बुनियादी ढांचे चुनौती देना शुरू कर दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2021 में उन्होंने बिटकॉइन को स्कैम और भविष्य की एक बड़ी आपद बताया था लेकिन तीन साल बाद राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि वह अमेरिका को "पृथ्वी की क्रिप्टो राजधानी" बनाना चाहते हैं, इसका उद्देश्य अमेरिका को डिजिटल एसेट्स के क्षेत्र में दुनिया का निर्विवाद नेता बनाना है। अमेरिका को क्रिप्टोकरेंसी का केंद्र बनाने के लिए जुलाई 2025 में जीनियस एक्ट पारित किया गया। यह क़ानून विशेष रूप से स्टेबलकॉइन और डॉलर से जुड़ी क्रिप्टोकरेंसी को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। इस क़ानून के बाद अब क्रिप्टोकरेंसी अमेरिका की मुख्यधारा की आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा बन चुकी है।

अमेरिका के वायोमिंग प्रान्त की सीनेटर सिंथिया लमिस और न्यूयार्क की सीनेटर किर्स्टन गिलिब्रैंड ने मिलकर इसका ड्राफ्ट तैयार किया, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों ने मिलकर फेडरल रिज़र्व स्टेबलकॉइन कानून को पास किया और मंजूरी दी हर स्टेबलकॉइन जारी करने वाली कंपनी को हर टोकन या कॉइन पर एक अनुपात एक में अमेरिकी ट्रेज़री का रिज़र्व बनाना होगा यह अनिवार्य शर्त थी, हर महीने स्टेबलकॉइन कंपनी का ऑडिट किया जाएगा ,बैंक सीक्रेसी एक्ट का अनुपालन, फेडरल रिज़र्व की जिम्मेदारी तथा उपभोग्ताओ के सुरक्षा ढांचा सुनिश्चित किया गया। इस कानून पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर के कुछ समय बाद नियमों में स्पस्टता आयी। ब्लैकरॉक ने पहला टोकेनाइज़ ट्रेजेरी फण्ड जारी किया, वीजा ने क्रॉसचेन यूएसडीसी सेटलमेंट सुरु किया, पे-पाल ने पीवाययूएसडी,सर्किल ने यूएसडीसी जारी करने वाली कंपनी का पहला आइपीओ आया। इस प्रकार स्टेबल कॉइन से किसी प्रकार से सम्बंधित कंपनियों ने कुछ वर्षों में ही 270 बिलियन डॉलर का कारोबार लगी। इन कंपनियों के अलावा एक कंपनी ने अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की वह थी टेथर। टेथर वर्तमान में विश्व में अमेरिकी बॉन्ड की सबसे बड़ी खरीदार है इसके पास 142 बिलियन डॉलर का रिजर्व है जो यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी की 120 बिलियन डॉलर से अधिक तथा दुनिया के 170 केंद्रीय बैंकों से अधिक है। अमेरिकी बॉण्ड की खरीददार एक अमेरिकी प्राइवेट कंपनी है 2025 में स्टेबल कॉइन का ट्रांजैक्शन 33 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का है जबकि विश्व की दो सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनी वीजा और मास्टर कार्ड के 24 ट्रिलियन डॉलर की लेनदेन से अधिक है। वीजा और मास्टर कार्ड के लेनदेन में कोल्ड ड्रिंक बर्गर खाद्य पदार्थों की होम

डिलीवरी के ट्रांजैक्शन भी जुड़ते हैं वही स्टेबल कॉइन के लेनदेन में सीमा पार का व्यापार, कॉर्पोरेट ट्रेजरी का प्रबंधन, रेमिटेंस की गणना शामिल रहती है अर्थात अब स्टेबलकॉइन मुख्य धारा की वित्तीय संरचना का अहम हिस्सा बन चुकी है। टेथर के सीईओ पॉल कहते हैं कि हम अमरिकी बॉन्ड के सबसे बड़े खरीदार हैं और इसका कारण वे लोग हैं जो अपने देश से दूसरे देशों में कामगार के रूप में, छात्र के रूप में, फैक्ट्री वर्कर्स के रूप में ,बिजनेस में टूरिज्म के रूप, में व्यापारियों की बड़ी संख्या के कारण हम अमेरिकी ट्रेजरी में सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं जीनियस एक्ट आने के बाद डॉलर की जरूरत अब प्रमुख मुद्रा के रूप में न होकर स्थानीय करेंसी में यूएसडीटी में परिवर्तनशीलता के सरल तरीकों के कारण हुई है l आधुनिक वित्तीय सिस्टम में एप्लीकेशन आधारित लेनदेन की व्यवस्था से मध्यवर्ती सेवा प्रदाताओं जैसे बैंक, ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट क्लर्क की भूमिका में बड़ी गिरावट आई है तथा यह लेन-देन कागजी डॉलर को छूता नहीं मगर कदम कदम पर स्टेबल कॉइन और टोकन के रूप में एंकर की भूमिका निभाता है जो भी इस आधुनिक प्रणाली का प्रयोग करके अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन करता है परोक्ष रूप से डॉलर की मांग सुनिश्चित तौर पर तैयार करता है इस व्यवस्था ने जहां वेस्टर्न यूनियन और स्विफ्ट वायर का कमीशन 5% से 8% के बीच था घटकर 0.1% कर दिया है तथा अंतरराष्ट्रीय सेटलमेंट का समय दिनों से घटकर कुछ घंटे हो गया है और इस सब की बुनियाद मेंअमेरिका के बॉन्ड और ट्रेजरी है l

डिजिटल सेवाओं और ऊर्जा के वैश्विक निर्यात से डॉलर की माँग का नया चक्र

1970 के तेल संकट के बाद अमेरिका में क्रूड ऑयल के निर्यात पर सख्ती थी। चार दशक बाद 2015 में ओबामा प्रशासन ने क्रूड ऑयल के निर्यात पर लगी पाबंदी को हटा दिया इससे अमेरिका का तेल और गैस का उत्पादन बढ़ा और आज अमेरिका विश्व में क्रूड ऑयल और गैस का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। अमेरिका प्रतिदिन 4.5 मिलियन बैरल और प्रतिवर्ष 1.64 बिलियन सालाना निर्यात करता है और 155 बिलियन क्यूबिक मेट्रिक टन लिक्वेफाइड नेचुरल गैस का प्रति वर्ष निर्यात कर रहा है तेल और गैस के यह सारे लेनदेन डॉलर में होते हैं जिससे डॉलर की मांग और बढ़ रही है l यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर तेल और गैस के निर्यात पर प्रतिबंध और होर्मुज की वैश्विक ऊर्जा सप्लाई में बाधा के कारण अमेरिका का तेल निर्यात बढ़ाना सुनिश्चित है क्योंकि दुनिया अभी भी क्रूड ऑयल और लिक्वेफाइड नेचुरल गैस के बिना नहीं चल सकती l आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार डिजिटल और तकनीकी सेवाओं का व्यापार अब मर्चेंडाइज गुड्स के व्यापार से बड़ा हो चुका है,डिजिटल और तकनीकी सेवाओं के निर्यात में आज अमेरिका के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि उसके पास डिजिटल और तकनीकी सेवाओं का संरचनात्मक विकास बहुत अच्छा है। आज अमेरिका में डिजिटल और तकनीकी सेवाओं का व्यापार लगभग 450 बिलियन डॉलर का है जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, डाटा सेंटर, डिजिटल एडवरटाइजमेंट, एआई,सीपीयू, एनवीडिया चिप,स्ट्रीमिंग सर्विसेज भी इसमें शामिल है। हाल फिलहाल में विश्व के तकनीकी परिवर्तनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज इन सभी का भुगतान अमेरिकी डॉलर में हो रहा है कुछ अमेरिकन तकनीकी सेवाएं इतनी महंगी है कि किसी देश की कंपनी अगर एक बार उनके उपयोग पर लागत खर्च कर दे तो दोबारा उसे लागत से हटकर अन्य कंपनियों के सेवाएं लेना संभव नहीं हो पता है l

निष्कर्ष

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस मौद्रिक व्यवस्था ने आकार लिया उसकी संरचना में डॉलर का प्रभुत्व मौजूद था lडॉलर और सोने की विनिमय दर के साथ 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ l इसी समझौते के साथ दुनिया की देशों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाने के लिए डॉलर को विदेशी मुद्रा भंडारों में शामिल करना शुरू किया 1960 के दशक में वियतनाम युद्ध और 1971 के निक्सन शॉक के समय डॉलर की विश्वसनीय संकट जरूर आया लेकिन तब तक डॉलर दुनिया की जरूरत बन चुका था 1973 में पेट्रोल डॉलर समझौते ने डॉलर को विश्व के ऊर्जा आयातक देश के करेंसी बास्केट में अनिवार्य रूप से शामिल हो चुका था। 1985 में प्लाजा एकार्ड के तहत डॉलर का 50 फ़ीसदी अवमूल्यन हुआ यही अवमूल्यन वैश्वीकरण की शुरुआत थी। समय के साथ वैश्विक जीडीपी में अमेरिका का हिस्सा घट रहा है लेकिन लेकिन मौद्रिक ताकत के रूप में डॉलर अभी भी विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में 60 फ़ीसदी है। इसी विदेशी मुद्रा भंडारों का निवेश अमेरिका में होता है यह निवेश यूरो, पाउण्ड तथा येन से कहीं अधिक है,अभी भी 80 फ़ीसदी निर्यात इनवॉइस तथा ग्लोबल बैंकिंग की 60 फ़ीसदी देनदारियां अभी भी अमेरिकी डॉलर में लेनदेन के रूप में मौजूद है। निवेश और पूंजी का चक्र अभी दशकों तक टूटता दिखाई नहीं देता है l 2015 में ओबामा प्रशासन द्वारा अमेरिका के तेल और गैस निर्यात पर लगी पाबंदी को हटाने के बाद आज अमेरिका विश्व में तेल और गैस का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तकनीकी आधारित सेवाओं के निर्यात में अमेरिका की कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां शामिल है तथा 2025 में जीनियस एक्ट पर हस्ताक्षर होने के बाद स्टेबल कॉइन को अमेरिकी ट्रेजरी से कानूनी मंजूरी मिल गई है इसके बाद अब डॉलर सिर्फ केंद्रीय बैंकों के विदेशी मुद्रा भंडारों के रिजर्व पेट्रोल डॉलर के बाद अब एप्लीकेशन आधारित लेनदेन तकनीक के माध्यम से लोगों तक दुनिया के कोने-कोने में पहुंचने को तैयार है l

सन्दर्भ सूची

https://www.bbc.com/hindi/articles/cdxkd0nzw70o
https://www.bbc.com/hindi/articles/cp3pedxkdr1o
https://www.bbc.com/hindi/articles/cy48l7k3dlpo
https://www.bbc.com/hindi/international-53474949
https://www.bbc.com/hindi/india-49470927
https://books.google.co.in/books/about/A_Treatise_on_Money.html?id=KnOkuAAACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.co.uk/books?id=xpw-96rynOcC&printsec=frontcover&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
https://www.bbc.com/hindi/india-51733608
https://stanfordreview.org/dollar-hegemony-americas-unnamed-empire/
https://americanaffairsjournal.org/2022/03/the-end-of-dollar-hegemony/
https://www.realinstitutoelcano.org/en/analyses/is-us-dollar-hegemony-under-threat/
https://www.project-syndicate.org/onpoint/is-the-us-dollar-s-global-hegemony-at-risk
https://www.academia.edu/42266667/Dollar_Hegemony
https://www.cfr.org/articles/future-dollar-hegemony
https://www.networkideas.org/2026/05/07/the-fractured-hegemony-of-the-dollar-system/
https://www.postkeynesian.net/downloads/working-papers/PKWP2220.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6448518
https://www.ft.com/content/d0e3bc97-b09e-4cc0-b4ec-4c28a0a1f2ed?syn-25a6b1a6=1
https://www.elibrary.imf.org/display/book/9798229017329/CH002.xml
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/18681026251342258

https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/the-international-role-of-the-u-s-dollar-2025-edition-20250718.html
https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/the-international-role-of-the-u-s-dollar-20211006.html
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20230319a.htm
https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/the-international-role-of-the-us-dollar-post-covid-edition-20230623.html
https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/the-international-role-of-the-us-dollar-post-covid-edition-accessible-20230623.htm#fig3
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2023-02-27/pricing-petroleum-in-china-s-yuan-sounds-inevitable-not-for-saudi-arabia
https://www.goldavenue.com/en/blog/newsletter-precious-metals-spotlight/new-brics-currency-what-impact-on-gold-and-the-dollar?srsltid=AfmBOorncdLJljz9l62EaPgzXVkrJPgEZZI274MQK5lcNVLKPf8ocJuW
https://www.brics2026.gov.in/about-us/
https://unctad.org/publication/two-decades-intra-brics-trade-trends-patterns-and-policies
https://unctad.org/publication/brics-investment-report
https://brics-plus-analytics.org/unctad-reports-on-brics-trade-figures/